



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

224-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022 (PAUSA 1, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 22nd December, 2022

No. 31-HLA of 2022/92/23857.— The Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 31-HLA of 2022

THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Act, 2022.
2. For clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, the following clause shall be substituted, namely:-
“(iv) to approve any incentives, relaxations, exemptions or grant clearances on the recommendations of the Empowered Executive Committee in mega projects and ultra mega projects beyond the package of fiscal incentives under any policy for industrial development or for industrial development of any sector in force as notified by the State Government from time to time;”.

Short title.

Amendment of
section 3 of
Haryana Act 6 of
2016.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government enacted Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, and corresponding rules, to create an ecosystem in which the Ease of Doing Business in the State matches and even exceeds the best global standards to reduce delays as well as the costs of doing business in the State. Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB) has been constituted under section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 and Empowered Executive Committee (EEC) has been constituted under section 4 of the said Act. Functions of Haryana Enterprise Promotion Board are given in section 3 (3) of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016. As per Clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Government was providing fiscal incentives to industries as per Enterprise Promotion Policy, 2015.

The State Government has notified new Industrial policy namely 'Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020' (replacing the Enterprise Promotion Policy which was valid till 31.12.2022) on 29.12.2020, which is effective from 01.01.2021 to 31.12.2025. The State Government is giving fiscal incentives to the industries of the state under this scheme now. Further, the State Government may announce new policy from time to time for promotion and development of industries or for industrial development of any sector.

In light of the above, clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 is proposed to be amended.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 22nd December, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 31-एच०एल०ए०

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022
 हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016,
 को आगे संशोधित करने के लिए
 विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात्:-
 2016 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 3 का संशोधन।
 "(iv) औद्योगिक विकास के लिए या किसी सेक्टर के औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित लागू पॉलिसी के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज के बाहर मेगा परियोजनाओं तथा अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में सशक्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर कोई प्रोत्साहन देने, रियायत देने, छूट का अनुमोदन करना या समाशोधन प्रदान करना;"।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने राज्य में एक इको सिस्टम बनाने के लिए जिसमें इज ऑफ डुइंग बिजनेस को अन्य राज्यों से मेल खाता हुआ व व्यापार शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी को कम करने एवं लागत को, वैश्विक मानकों से भी कम करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 व संबंधित नियम बनाये थे। हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है। हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड के कार्यों का विवरण हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 3 उप धारा (3) में दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 उप धारा (3) खंड (iv) के अनुसार, सरकार उद्योगों को उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही थी।

राज्य सरकार ने दिनांक 29.12.2020 को 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020' (31.12.2020 तक मान्य उद्यम प्रोत्साहन नीति के स्थान पर) नई औद्योगिक नीति अधिसूचित की है, जो 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी है। राज्य सरकार इस योजना के तहत अब राज्य के उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। आगे, राज्य सरकार उद्योगों के संवर्धन एवं विकास अथवा किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए समय-समय पर नई नीति की घोषणा कर सकती है।

उपरोक्त के आलोक में, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 3 उप धारा (3) खंड (iv) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।